by the Government since the announcement of New Industrial Policy till 31-3-1994, have been approved. These involve NRI investment of about Rs. 2219.76 crores in various sectors like hotel, newsprint, computer software, textiles, food processing, electronics, etc.

Location of NRI investment approvals is not centrally maintained.

Proposal from Pepsi-co for investment in India

7007. SHRI AHMED MOHAMED BHAI PATEL:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a proposal of PEPSI-CO Inc, US, to set up a 100 per cent holding company in India, a joint venture with Britain gas for piping gas to house hold and industrial units in greater Bombay and setting up of a wind energy park in Gujarat are among the 50 foreign investment proposals cleared by Government up-to end of February, 1994;

(b) if so, what will be the total investment made on these projects;

(c) what are the countries and the projects that are going to be set up in India; and

(d) the total investment made by them in each plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) Yes, Sir. The Empowered Committee on Foreign Investment at their meeting held on 14th February, 1994 had approved 50 proposals for foreign direct investment recommended by the Foreign Investment Promotion Board. The total foreign direct investment envisaged in the projects was Rs. 617.51 crores. Details of each of the proposals approved namely name of the Indian Company, name of the foreign collaborator and the country to which he belongs, item of manufacture and amount of foreign investment are given in the annexure. (*See* Appendix 170, Annexure No. 140).

मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए लघु उद्योग

7008. श्री गोविन्दराम सिरो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस संबंध जिलेवार कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये है ;

(ख) इन उद्योगों में से कितने उद्योग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों से संबंधित हैं और इन उद्योगों में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इस उद्योगों के उत्पादों के विपणन के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ; और

(घ) क्या कुछ उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) के कार्य क्षेत्र में आने वाले 1,87,227 लघु एककों को 31 दिसम्बर, 1992 तक स्थायी आधार पर पंजीकृत किया गया था । इन एककों के जिले-वार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं (नीचे देखिए) ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के स्वामित्व वाले उद्योगों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित वर्तमान आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं । तथापि विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा संदर्भ वर्ष 1987–88 के लिए 1989—91 के दौरान की गई लघु औद्योगिक एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार राज्य उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीकृत 76218 लघु एककों को 31 मार्च, 1988 को कार्य

करते हुए पाया गया था । इनमें से क्रमशः 9409 और 4818 एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व में थे। इन उद्योगों में 1,58,808 व्यक्तियों को रोजगार मिला था जिनमें से 21, 997 व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा 15,245 व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे ।

(ग) विपणन मुख्यतः एक उद्यमियता कार्य हैं । तथापि लघु उद्योगों के कारण आधार को देखते हुए सरकार ने सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम के अधीन ही खरीरदारी के लिए 409 मदों का आरक्षण कर दिया है और एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पंजीकृत लघु एककों को निम्नलिखित विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध करायी है

1. टेन्डर सेट मुफ्त जारी करना ।

2. धरोहर राशि के भुगतान से छूट ।

3. उस वित्तीय सीमा तक प्रतिभूमि जमा को समाप्त करना जिसके लिए एकक पंजीकृत है ।

4. गुणदोष के आधार पर बड़े एककों को मूल्य तालिका से 15 प्रतिशत अधिक तक मूल्य में वरीयता देना ।

मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें अपने स्वयं के नीतिगत उपायों के अधीन लघु एककों को राज्य खरीद कार्यक्रम के तहत उनके उत्पादों की बिक्री में सहायता करती है ।

(घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1992 के अन्त में मध्य प्रदेश राज्य में 22,333 लघु रुग्ण एकक थे । जीव्यक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास के उपाय राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति और राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति के माध्यम से नियमित आधार पर किये जा रहे हैं । जीव्यक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास में बैंक भी नियमित आधार पर सहायता कर रहे हैं । ऐसे जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रु० से अधिक नहीं है नाम मात्र के 1 प्रतिशत वार्षिक सेवा प्रभार की दर से राष्ट्रीय इक्विटी निधि से 1,50,000 रु० तक दीर्घकालीन इक्विटी किस्म की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है । लघु औद्योगिक एककों की रुग्णता की समस्या से तेजी से निपटने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि रुग्ण औद्योगिक एककों का कार्य देखने और तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रकोष्ठों की स्थापना करनी चाहिए

विवरण

मध्य प्रदेश में 31–12–1992 तक पंजीकृत सीडो एककों को जिलेवार सूचयी संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	31–12–1992 को एककों की संचयी संख्या
1.	खंडवा	4694
2.	खरगोन	7847
3.	झाबुआ	1043
4.	इंदौर	6317
5.	धार	2599
6.	पीतमपुर	349
7.	देवास	2775
8.	उज्जैन	5463
9.	मंदसौर	5985
10.	शाजापुर	2439

11.	रतलाम	2874	35.	गुना	3156
12.	सेहोर	2149	36.	ग्वालियर	5390
13.	भोपाल	4728	37.	दतिया	1539
14.	राजगढ़	3135	38.	मालनपुर	472
15.	रायसेन	2012	39.	शिवपुरी	2845
16.	मंदीप	220	40.	रेवा	3002
17.	विदिशा	2651	41.	सतना	4516
18.	बेतुल	2920	42.	सिधी	1912
19.	होशगाबाद	4484	43.	शडडोल	3054
20.	रायपुर	10585	44.	सागर	3293
21.	दुर्ग	9980	45.	छत्तरपुर	3001
22.	राजनन्दगांव	3293	46.	टीकमगढ़	1867
23.	जगदलपुर	3360	47.	पन्ना	1948
24.	बिलासपुर	5987	48.	दमोह	2135
25.	रायगढ़	7720			
26.	अंबिकापुर	5641		योग :	187227
27.	नरसिंहपुर	2500			
28.	मान्डला	5064			
29.	सिवनी	3811			
30.	जबलपुर	9219			
31.	बालाघाट	2889			
32.	छिंदवाड़ा	3762			
33.	भिन्ड	5666			
34.	मोरेना	3936			

Foreign capital inflow

7009. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the actual inflow of foreign investments in 1993 amounted to Rs. 11.22 billion if so, what was comparative amount/names of investing countries in India during 1994-95, country-wise till date;

(b) whether China plans to invest $ 1 billion India if so, what are the sectors in which investment has been finalised so far; and